# Popular Front of India

**G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindikunj, Noida Road, New Delhi- 110025**
**website: www.popularfrontindia.org email:popularfrontmail@gmail.com Tel: 011- 29949902**

**प्रेस रिलीज़**

नई दिल्ली
14 नवम्बर 2017

## बाबरी मस्जिद विध्वंस की 25वीं बरसी पर पॉपुलर फ्रंट ने दोहराई उसी जगह पर मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की दो दिवसीय बैठक केरल के कालीकट में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन ई. अबूबकर ने की। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये गए:

### कहीं हम भूल न जाएं

संघ परिवार के द्वारा बाबरी मस्जिद गिराए जाने की 25वीं बरसी के मौके पर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद ने सभी भारतवासियों से उसी जगह पर मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग के साथ इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने की अपील की। एक ऐतिहासिक मस्जिद के विध्वंस, जहाँ अयोध्या के मुसलमान 463 वर्षों से नमाज़ पढ़ते आ रहे थे और देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बाबरी मस्जिद को सोचे समझे और मंसूबाबंद विध्वंस से बचा पाने में नाकामी ने पूरे देश का सर शर्म से झुकाया है। यह दर्दनाक दुर्घटना इतनी बड़ी दुर्घटना थी कि इसके तुरंत बाद ही सरकार और सभी सेक्युलर दलों ने एक आवाज़ में मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की। लेकिन एक चौथाई सदी गुज़रने के साथ, जहाँ संघ परिवार के इशारों पर चलने वाली केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मस्जिद की जगह पर मंदिर के निर्माण की कोशिशें तेज़ कर दी हैं, वहीं सेक्युलर वर्ग बड़ी आसानी से इस मामले को हाशिये पर डालता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे समय में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बल देते हुए कहा कि, क्योंकि बाबरी मस्जिद को न्याय दिलाना केवल मुसलमानों की समस्या नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है, इसलिए सभी भारतीय नागरिकों को मुसलमानों के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की पूरी ताकत से मांग करनी चाहिए।

### नोटबंदी और जीएसटी की तबाहियों से जनता को बचाओ

बैठक ने इस बात की ओर इशारा किया कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को एक साल पूरा हो चुका है, जो अपने बताए गए उद्देश्य काले धन को खत्म करने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। कैश तो काले धन का एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी इस बात की पुष्टी की जा चुकी है कि प्रतिबंधित मुद्रा का 98.8 प्रतिशत हिस्सा वापस आ चुका है, अर्थात 0.01 प्रतिशत काला पैसा भी खत्म नहीं हुआ है। इस बेनतीजा कार्यवाही के कारण जनता को इस तरह परेशानियों में डालने के लिए केंद्र सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। यही मामला जीएसटी को लागू करने का भी है। इससे किसी भी चीज़ की कीमत में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसके कारण उपभोक्ताओं के शोषण के और ज़्यादा रास्ते पैदा करके कीमतों में उछाल का आम माहौल बन गया है। बैठक ने आगामी चुनावों के दबाव में जीएसटी की दरों में कमी लाने के हालिया कदम का स्वागत किया, और इसे जनविरोध की जीत करार दिया।

## असम में अल्पसंख्यकों को परेशान करना बंद करो

पॉपुलर फ्रंट की कार्यकारिणी परिषद ने सभी विपक्षी दलों और मानवाधिकार समूहों से असम के बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को परेशान किये जाने की घटनाओं को रोकने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है, जो कि नागरिकों के राष्ट्रीय पंजीकरण (एनआरसी) को पूरा करने की आखरी हद, 31 दिसम्बर के मद्दे नज़र अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने लगभग पचास लाख भारतीय नागरिकों को ''गैरकानूनी प्रवासी'' की श्रेणी में डालकर, उन्हें ''विदेशी'' बताकर और उन्हें ''बांग्लादेशी'' तथा ''डी–वोटर'' बोलकर उन्हें परेशान करने की मुहिम तेज़ कर दी है। असम में बसे हज़ारों बंगाली बोलने वाले लोगों को क़ैद में डालने या देश से निकालने के द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है। बैठक ने असम में चल रही इन कार्यवाहियों को मानवता की तबाही करार देते हुए कहा कि असामी लोगों की इस दुर्दशा को एक राष्ट्रीय मामले के तौर पर लिया जाना चाहिए।

## गुजरात में बीजेपी के खिलाफ विशाल गठबंधन पर ज़ोर

गुजरात विधानसभा चुनाव के माहौल में उभरते राजनीतिक रूझानों को सामने रखते हुए, पॉपुलर फ्रंट ने कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी सरकार में अत्याचार का शिकार रहे समूहों और समुदायों के बीच उभरते विशाल गठबंधन का स्वागत किया है। कांग्रेस, पाटीदार, ठाकुर और दलित नेताओं के बीच की आपसी चुनावी समझ को और ज़्यादा फैलाते हुए इसमें अल्पसंख्यकों व अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया जाना चाहिए। बैठक ने कहा कि गुजरात में जात और बिरादरी से ऊपर उठकर जनता का यह गुस्सा, बीजेपी के विभाजनकारी साम्प्रदायिक राजनीति के सर पर मंडलाते पतन का इशारा है।

## एनएसए को वापस लो और भीम आर्मी चीफ को जेल से रिहा करो

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भीम आर्मी चीफ चंद्र शेखर आज़ाद रावन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत दिये जाने के तुरंत बाद ही उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा ऐक्ट (एनएसए) जैसा सख्त कानून लगाने की उत्तर प्रदेश सरकार की घटिया कार्यवाही की निंदा की है। आज़ाद 'रावन' को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए उठाए गए इस कदम के द्वारा बीजेपी यह संदेश देना चाहती है कि यह ब्रह्मणवादी पार्टी किसी दलित आंदोलन को इतनी आसानी से फलने फूलने नहीं देगी, भले ही यह खुद को दलितों के मसीहा के तौर पर पेश करते हैं।

## विशाल जनसभाओं की सफलता जनता के समर्थन का सबूत

पॉपुलर फ्रंट की एनईसी ने पिछले महीने विभिन्न राज्यों में आयोजित विशाल जनसभाओं में हज़ारों की संख्या में आई जनता को सलाम पेश किया है। बड़ी संख्या में जनता का भाग लेना और विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी के साथ जनसभाओं को मिली बड़ी सफलता इस बात का सबूत देती है कि जनता पॉपुलर फ्रंट के साथ सशक्तिकरण की राह में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैठक ने यह आशा जताई कि अब से पॉपुलर फ्रंट के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाने वाली ताकतें दीवारों पर लिखी पंक्तियों को पढ़ने में होशियारी दिखाएंगी और इस आंदोलन और इसके आदर्शों के प्रति सही सोच और नज़रिये को बढ़ावा देंगी।

मुहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया